आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 28.02.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
- प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत देहरादून जिले के दूरस्थ सरकारी स्कूलों में नया फर्नीचर उपलब्ध कराया गया।
- ऋषिकेश में कल से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, देश–विदेश के 20 हजार से अधिक योग साधकों के जुटने की उम्मीद।
- उत्तराखंड में आज कहीं–कहीं भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी।
- हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने हर की पैड़ी क्षेत्र में प्लास्टिक और पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिये।

रिपोर्ट

उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के संबंध में गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आयोग ने इससे पहले 14 अगस्त 2022 को हरिद्वार जिले की पहली रिपोर्ट सौंपी थी, और अब शेष 12 जिलों की तृतीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी को समुचित प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत के वार्ड, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत वार्ड, ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत के वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की गई है।

नया फर्नीचर

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में संचालित प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत देहरादून जिले के दूरस्थ सरकारी स्कूलों में नया फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर और सुविधाजनक शैक्षिक माहौल मिलेगा। ओएनजीसी देहरादून के सहयोग से इन स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। अब तक, विभिन्न स्कूलों में 335 टेबल और कुर्सियां वितरित की जा चुकी हैं।

इस बीच, प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत, हुडको द्वारा स्कूलों में पठन–पाठन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाने का कार्य अंतिम चरण में है।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि सरकारी स्कूलों के विकास और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत आगे भी जरूरतमंद स्कूलों को फर्नीचर और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

भूकानून

राज्य सरकार का भू–कानून इन दिनों सुर्खियों में है। इसके कड़े प्रावधानों के कारण राज्य में भूमि की अत्यधिक खरीद पर नकेल कसने की उम्मीदें बढ़ी हैं। अब सरकारी मशीनरी इन नए प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था बनाने में जुट गई है, जिससे भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान और बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि अतिक्रमण पर रोक लग सके।

इस संशोधित भू–कानून के तहत, अब बाहरी व्यक्तियों को कृषि और बागवानी के लिए पर्वतीय जिलों में भूमि खरीदने की छूट पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में यह छूट थोड़ी देर के लिए बनी रहेगी, लेकिन यहां भी भूमि खरीद प्रक्रिया को कड़ा किया गया है। इन जिलों में बाहरी व्यक्ति को अब जिलाधिकारी के बजाय शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

नए प्रावधानों के तहत, नगर निकाय और छावनी परिषद क्षेत्रों से बाहर भूमि खरीदने वाले बाहरी व्यक्तियों को केवल 250 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीदने की अनुमति होगी, और इसके लिए उन्हें शपथ पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त, भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू–उपयोग के अनुसार किया जाएगा, और उल्लंघन पर संबंधित भूमि राज्य सरकार के अधीन ले ली जाएगी। भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, और जिलाधिकारी को नियमित रिपोर्टिंग करनी होगी।

उच्च न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वह प्रदेश में हाल ही में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में आवश्यक बदलाव करने के लिए तैयार है। यह सवाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान किया, जिसमें यूसीसी में लिव इन संबंधों से संबंधित प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

इससे पहले, यूसीसी को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था। इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर एक अप्रैल को सुनवाई होगी।

जनहित याचिका में भी लिवइन पंजीकरण फार्म में सूचनाएं मांगे जाने पर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रावधान युगल की निजता का उल्लंघन करता है।

बैठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष क्षेत्र की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में कल उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने, औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और पारंपरिक चिकित्सा में अग्रणी के रूप में देश की वैश्विक स्थिति बढ़ाने में क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान देने के साथ आयुष क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रशिक्षण

अल्मोड़ा जिले में केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान ने सल्ट के हरडा और मौलेखाल में महिलाओं को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया। इसका उद्देश्य महिलाओं को घर से रोजगार देकर पलायन रोकना है। इस दौरान महिलाओं को बंजर भूमि पर रोज मैरी की खेती कर आजीविका बढ़ाने के तरीके सिखाए गए। वहीं रूद्रपुर के सितारगंज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उद्यमिता विकास कार्यक्रम में छात्रों को स्वरोजगार के लिए टिप्स दिए गए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय उत्पादों और हस्त कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिभागियों को मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती बनाने, शहद उत्पादन, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

मौसम

उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में कल शाम से बर्फबारी का दौर जारी है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

चारधाम सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है। इस बीच, मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ऊंचाई वाले हिस्सों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही राजधानी देहरादून सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव

ऋषिकेश में कल से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष योग महोत्सव ग्रीन थीम पर केंद्रित रहेगा। सात मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में देश–विदेश के 20 हजार से अधिक योग साधकों के जुटने की उम्मीद है। महोत्सव के दौरान हर दिन योगाचार्य प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराएंगे। शाम को सांस्कृतिक आयोजन होंगे, जिससे कार्यक्रम और भी बेहतर बनने की आशा है।

महोत्सव में प्रतिभाग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण किए जा रहे हैं। ऑनलाइन पंजीकरण जीएमवीएन की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है।

तीन दशक से अधिक समय से आयोजित हो रहे इस महोत्सव में हर साल हजारों योग साधक जुटते हैं। पिछले वर्ष 42 देशों के 890 विदेशी प्रतिभागियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था।

प्लास्टिक प्रतिबंध

हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने हर की पैड़ी क्षेत्र में प्लास्टिक और पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। गंगा संरक्षण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने प्लास्टिक बेचने वाले के खिलाफ भी सख्त कारवाई करने को कहा। उन्होंने शहर में अतिक्रमण रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं।

स्वीकृति प्रदान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा स्थित चकरपुर स्टेडियम छात्रावास में बोर्डिंग बॉक्सिंग एकेडमी स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 11 फरवरी को चकरपुर स्टेडियम उधमसिंह नगर में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित मलखंब प्रतियोगिता के अवसर पर बोर्डिंग बॉक्सिंग एकेडमी स्थापित घोषणा की थी।

नीति आयोग

नीति आयोग ने कहा है कि भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर है। वर्ष 2025 में देश का सकल घरेलू उत्पाद–जीडीपी चार दशमलव तीन ट्रिलियन डॉलर हो गया है। नीति आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए कहा कि भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2015 में दो दशमलव चार ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 में चार दशमलव तीन ट्रिलियन डॉलर हो गया।

भर्ती विज्ञापन जारी

चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग पदों के लिये राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है।

विभागीय समीक्षा

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला पंचायत की विभागीय समीक्षा बैठक में जिला पंचायत की ओर से राज्य वित्त, 15वां वित्त एवं दैवीय आपदा के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के तहत कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों को योजनाओं का अन्य विभागों की योजना के साथ दोहराव न होने की हिदायत दी।